Telangana Today- 20- October-2022

Centre urged to clear DPRs

STATE BUREAU
Hyderabad

Expressing concern over the inordinate delay in granting Technical Advisory Committee (TAC) clearance to the Detailed Project Report of Godavari basin projects in the State, the Telangana government has urged the Jal Shakti Ministry to immediately take steps for expeditious approval of the DPRs.

Special Chief Secretary (Irrigation) Rajat Kumar on Wednesday wrote a letter to Jal Shakti Ministry asking it to speed up the TAC clearance process for three projects, whose DPRs has been cleared by the Central Water Commission in March this year.

The State submitted six DPRs on Sita Rama Lift Irrigation Scheme Sammakka Sagar Project (Thupakulagudem project), Mukteshwar (Chinna Kaleshwaram) LIS, Chowtpally Hanumanth Reddy LIS Modikuntavagu Project and Chanaka-Korata barrage on the Godavari to the CWC, out of which three DPRs were cleared by it.

The DPRs of Chanaka-Korata barrage, Choutpally Hanumanth Reddy LIS and Mukteshwar (Chinna Kaleshwaram) LIS to Godavari River Management Board (GRMB) is pending with Centre.

The Times of India- 20- October-2022

India to assess WB appointing expert on water dispute with Pak

New Delhi: In a guarded response to the World Bank's announcement to concurrently appoint a neutral expert and also a chair of the court of arbitration to address differences between India and Pakistan over the Kishenganga and Ratle projects, the government said Wednesday India will assess the matter.

The government said it had noted the decision by the World Bank and also its own admission in the announcement that carrying out two processes concurrently poses legal and practical challenges. In an official statement, the government reminded the World Bank India India believes that the implementation of the Indus Water Treaty (IWT) must be in "letter and spirit of the Treaty".

"Recognising the World Bank's admission in its announcement that carrying out two processes concurrently poses practical and legal challenges, India will assess the matter," it said.

India and Pakistan signed the IWT in 1960. TNN

Rashtriya Sahara- 20- October-2022

पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा सवाल

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट डॉ. शशांक द्विवेदी

विश्व वन्यजीव कोष (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) द्वारा जारी 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022' के अनुसार वैश्विक स्तर पर 1970 से 2018 के बीच 48 वर्षों के दौरान वन्य जीवों की आबादी में 69 फीसदी की कमी दर्ज की गई। 2022 के लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (एलपीआई) में वन्य जीवों की 5230 प्रजातियों के 32,000 जीवों की संख्या का विश्लेषण किया गया। इंडेक्स 50 वर्षों से स्तनधारी जीवों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और उभयचरों की संख्या ट्रैक कर रहा है।

साल के अंत में दुनिया के कई देश मॉन्ट्रियल में जैव विविधता की रक्षा के लिए नई वैश्विक योजना तैयार करने के लिए मिलने वाले हैं। उससे पहले आई रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सच्चाई यह भी है कि जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के जितने भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और कार्यक्रम होते हैं, उनमें विकासशील व विकसित देशों के बीच आर्थिक मुद्दों पर विवाद होता है। विकसित देश अधिक जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि विकासशील देश ही जैव विविधता दुनिया में गर्म होती जलवायु, कम होते जंगल, विलुप्त होते प्राणी, प्रदूषित होती नदियों, सभी को बचाने का काम करें। यहाँ तक कि इन कामों के लिए वे पर्याप्त आर्थिक मदत देने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जैव विविधता के लिए आधुनिक विकास और प्रकृति संरक्षण, दोनों के बीच संतुलित तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है । नहीं तो इसका खमियाजा प्रकृति को भुगतना पड़ेगा। वस्तुतः कोरोना का वैश्विक संकट इसका ही नतीजा था और अभी भी बरकरार है। जीव-जंतुओं और पौधों की लगभग 50 प्रजातियां रोजाना विलुप्त हो रही हैं। हमारे पूर्वज पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक प्रबंधन में माहिर थे। उनके संस्कार जनित प्रयासों से ही हम जैव विविधता बचा पाए हैं, और प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए सबकी जरूरत पूरा करते रहे। पर्यावरण का निरंतर क्षरण रोज की बात है पर अब तो दुनिया भर में पाए जाने वाले पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं की करीब तिहाई प्रजातियां भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। एक तरफ मानवीय जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वहीं मानव जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को नष्ट कर उनकी जगह भी पसरता जा रहा है। वास्तव में जैव

विविधता के संरक्षण बिना विकास का कोई महत्व नहीं है।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अनुसार ताजे पानी के इलाकों में जैव विविधता में ज्यादा कमी आई है. ताजा पानी धरती के महज 1 प्रतिशत हिस्से पर मौजूद है। मगर दुनिया की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ताजे पानी के 3 किमी. के दायरे में रहती है। ऐसे में बढ़ती मानव आबादी का दबाव बाकी जीवों पर आएगा ही। इसी दबाव के कारण जलचरों की आबादी में 83 % की कमी आई है। जंगलों की ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की भूमिका के बारे में हम सभी जानते हैं। दुनिया भर के जंगल वातावरण से 7.6 गीगा टन कार्बन डाई ऑक्साइड सोखते हैं। ये मानव गतिविधियों से दुनिया में पैदा हुई कार्बन का 18 प्रतिशत होती है। जंगल कुल मिलाकर इस धरती को 0.5 डिग्री ठंडा रखते हैं। मगर इसके बावजूद हम 10 मिलियन हैक्टेयर जंगल हर साल खो देते हैं। इसका मतलब है कि हम हर साल एक पुर्तगाल खो रहे हैं। भारत में जैव विविधता सबसे ज्यादा है। देश की आधी आबादी को कृषि से रोजगार मिल रहा है। यह हमारी सोच में होना चाहिए कि जीव-जंतुओं का महत्त्व हमसे कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि सभ्यता और संस्कृति का बड़ा महत्व है। दुनिया को मिल कर जानना चाहिए कि कौन से प्रयास बेहतर हैं, जिनको और जगह भी अपनाया जा सकता है। विश्व की बढ़ती आबादी की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में कृषि जैव विविधता के संरक्षण से टिकाऊपन बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास जरूरी है ।

जैव विविधिता की चिंता अकेले किसी एक देश अथवा महाद्वीप की समस्या है। न ही कोई अकेला देश इस समस्या से निपटने के उपाय कर सकता है। वैश्विक समुदाय को जैव विविधिता संकट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, और यह समस्या भी वैश्विक समुदाय की ही है। इसलिए सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मिल जुलकर समस्या से निपटने के रास्ते तलाशें और जैव विविधिता को संरक्षित करने वाली योजनाओं को क्रियान्वित करें। आरंभ में विकास और जैव विविधिता को दो अलग-अलग अवधारणा के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाद में महसूस किया गया कि विकास और जैव विविधिता को अलग-अलग हिस्से नहीं माना जा सकता। जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास के साथ ही जनता की सकारात्मक भागीदारी भी जरूरी है। जनजागरूकता होने पर ही जैव विविधता संरक्षण हो पाएगा। जैव विविधता के संरक्षण का सवाल पृथ्वी के अस्तित्व से जुड़ा है। इसलिए विश्व के जीन पूल को कैसे बचाया जाए इस पर पूरी दुनिया को गंभीरता से विचार करते हुए ठोस निर्णय लेना होगा।

Hindustan- 20- October-2022

पाकिस्तान से जल विवाद का आकलन करेगा भारत

- भारत-पाक में 1960 में हुई थी सिंधु जल संधि
- विश्व बैंक ने स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त किया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने बुधवार को कहा कि वह किशनगंगा और रातले पनबिजली ऊर्जा परियोजना से जुड़े मामले का आकलन करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच दो परियोजनाओं को लेकर विवाद है, जो 1960 के सिंधु जल संधि के तहत आता है।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 'हमने किशनगंगा और रातले पनबिजली ऊर्जा परियोजना से जुड़े मामले में समवर्ती रूप से स्वतंत्र विशेषज्ञ और न्यायधिकरण अदालत की एक पीठ नियुक्त करने की विश्व बैंक की घोषणा को देखा है।' विश्व बैंक ने 1960 की सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच असहमति और मतभेदों को देखते हुए किशनगंगा और रातले जलविद्युत संयंत्रों के संबंध में मध्यस्थता न्यायालय की पीठ और एक तटस्थ विशेषज्ञ को नियुक्त किया है।

मंत्रालय की ओर कहा गया कि विश्व की घोषणा में दो प्रक्रियाओं के साथ-साथ होने के बुनियादी एवं कानूनी चुनौतियां होने की बात स्वीकार करने के मद्देनजर भारत इस मामले का आकलन करेगा।